pharmaceuticals has not exceeded the limits mentioned in Schedule to DPCO, 1987 in case of almost all the companies listed in the reply to the Starred Question No. 147 answered in the Rajya Sabha on 3.12.1992, during 1990-91 or 1991-92.

(b) Investment proposals of these companies of Rs. 30.34 crores, Rs. 34 crores, Rs. 43 crores, Rs. 99.14 crores and Rs. 6.95 crores were approved during 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92 respectively.

(c) and (d): There is no requirement in the Drugs (Prices Control) Order, 1987 for ploughing back the profit earned by a pharmaceutical company. No instance of these companies suppressing or siphoning off profits in the manner indicated has come to the notice of the Government.

(e) The factors/necessitating review of the existing Drug Policy have been indicated in the Background Note on Review of Drug Policy, 1986 which has been laid on the tabic of both the Houses of Parliament on 12.8.1992.

Disposal of Nuclear Waste

372. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any plan for the disposal of nuclear wastes; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) Right from the inception of the nuclear programme in India, management of nuclear waste has been an integral part of the overall R&D programme in the full nuclear fuel cycle, and given due importance. The main thrust in the management of nuclear waste has been to ensure safety of the human life and environment. This is achieved by scrupulously following the regulatory guidelines of the Atomic Energy Regulatory Board consistent with international practices and applying appropriate technologies for dealing with the nuclear wates right from the point of generation in various parts of the nuclear fuel cycle to their processing, conditioning and disposal. India has fully developed indigenous technology in this regard and also participates in various expert groups at the international level. India is also a member of the International Waste Management Advisory Group of the International Atomic Energy Agency.

देश में परमाणु ऊर्जा के विकास की योजना

373. श्री गया सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु ऊर्जा के विकास के संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार बिहार जैसे पिछड़े राज्य में परमाणु ऊर्जा का विकास करने के संबंध में कोई योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) भारत ने परमाणु ऊर्जा को कई प्रकार के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में काम में लाने के संबंध में स्वदेशी क्षमता हासिल कर ली है। इस समय परमाणु बिजलीघरों की स्थापित विद्युत क्षमता 1720 मेगावाट है। जिन स्कीमों को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है उनके पूरा होने पर यह क्षमता चालू योजना के अन्त तक 2820 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। नाभिकीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग बिजली पैदा करने के अलावा बहुत से विकास कार्यों जैसे कि चिकित्सा, कृषि और उद्योग में रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग, खाद्य-पदार्थों के परिक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग, औषध भेषजों तथा अन्य चिकित्सा उत्पादों का विकिरण द्वारा निर्जर्मीकरण, रोगों के निदान के लिए रेडियोइम्यूनो ऐसे तकनीकों का प्रयोग, उद्योग में गामा रेडियोग्राफी का उपयोग, जीवाणु आदि नष्ट करने के लिए जल-मल का विकिरण द्वारा संसाधन करने के लिए किया जा रहा है।

(ख) बिहार में जादुगुड़ा में यूरेनियम की खान कई वर्षों से काम कर रही है। बिहार में नरवापहाड़ में यूरेनियम की खानों को विकसित करने की परियोजना मंजूर हो गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता चूंकि अधिक है,